IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

प्रजातंत्र में मिली–जुली सरकारें : एक अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी एवं पूनम विश्वकर्मा

प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांशः–

भारतीय राजनीति में संयुक्त या मिली–जुली सरकार कोई अनजाना शब्द नहीं। खासकर प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार पूर्व से ही इसी आधार स्तंभों पर चलती आ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चतुर्थ आम निर्वाचन के पश्चात् ''मिली–जुली सरकारों की राजनीति'' को एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है। वर्तमान समय के परिदृश्य में मिली–जुली सरकारें भारत के लोकतंत्र की आवश्यक जरूरत एवं नियति बन गई हैं। जब समाज गहरे संक्रमण के दौर से गुजरता है तो गठबंधन आवश्यक हो जाता है। मिली–जुली सरकारों के समकालीन परिदृश्य को देखें तो जहाँ कुछ वर्ष पहले केन्द्र एवं राज्य स्तर पर त्रिशंकु तथा एक कमजोर लोकसभा का उद्भव हो रहा था, वहीं कुछ वर्षों में मजबूत गठबंधन सरकारों का निर्माण हो रहा है जिसके फलस्वरूप सरकारों का वास्तविक स्वरूप व्यक्तिगत होता जा रहा है। गठबंधन या मिली–जुली सरकारों का सत्तारूढ़ होना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अस्वस्थ अथवा दोषपूर्ण परम्परा नहीं है। भारत में मिली–जुली सरकारों का उद्भव एक दलीय प्रभुत्व का पतन, दलों में अनुशालीनता का अभाव एवं दलीय नेतृत्व वाले व्यक्तियों के नेतृत्वात्मक प्रभाव में कमी के कारण हुआ है। इस गठबंधन के अनूठे प्रयोग के परिणामस्वरूप ही संक्रमण काल में राष्ट्र को एक नई दिशा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसलिए संयुक्त या मिली–जुली सरकार अपरिहार्य है अर्थात् चाही या अनचाही मिली–जुली सरकार देश की नियति बन गई है।

मूल शब्दः– प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, गठबंधन, बहुदलीय प्रणाली ।

प्रस्तावना –

"भारतीय संसदीय[1] परम्परा एवं संविधानुसार सरकारों का निर्माण दलगत आधार पर ही होता है।'' जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही दल सरकार बनाती है, केन्द्र सरकार के लिए लोकसभा में बहुमत होनी चाहिए, वहीं राज्य सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत वाले दल सरकार बनाते हैं, परन्तु यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से मिली–जुली सरकार बनाती है।[2] भारत में साझा सरकारों की उत्पत्ति के मूल में भारतीय संस्कृति की विविधतापूर्ण प्रकृति भी उत्तरदायी कारक है। भारत में विद्यमान सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों व बहुदलीय व्यवस्था के कार्य–कारण की पृष्ठभूमि में गठबंधन सरकारों की आवश्यकता एवं अनिवार्यता देखने को मिलती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

मिली–जुली सरकार का अर्थ –

'गठबंधन'[3] शब्द लैटिन शब्द 'कोलिटियो' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'एक साथ बढ़ना'। इस प्रकार, तकनीकी रूप से, गठबंधन का तात्पर्य कई भागों को एक निकाय या पूरे में एकजुट करने के कार्य से है। राजनीतिक रूप से, गठबंधन का अर्थ विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन है।

ऑग के अनुसार[4]–

''मिली–जुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है, जिसमें विभिन्न सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमण्डल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं।'' मिली–जुली सरकार राजनीतिक समुदायों तथा शक्तियों का गठजोड़ है, जो अस्थायी और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है।

गठबंधन सरकार के सकारात्मक पक्ष –

1. गठबंधन सरकार में शामिल राजनीतिक दलों में परस्पर सहयोग की भावना होती है।
2. इसमें विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल साथ आकर, सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों में फैली दूरिया या वैमनष्यता को कम करते हैं।
3. एक दल अपनी निरंकुशता नहीं थोप सकता क्योंकि सामूहिक सहमति बनाना आवश्यक होता है।
4. संघात्मकता को अधिक प्रासंगिक बनाता है, जिससे संघीय और प्रादेशिक स्तर पर सौहार्द्र व समन्वय के साथ बेहतर समझ निर्मित होती है।
5. सरकार निरंकुश नहीं बन पाती।
6. दूसरे दलों के अनुभवी व योग्य राजनीतिक व्यक्तियों का लाभ सरकार को मिलता है।

गठबंधन सरकार के नकारात्मक पक्ष[5] –

1. गठबंधन सरकार का पहला दोष है कि वे अस्थिर है या अस्थिरता की ओर प्रवृत्त हैं।
2. गठबंधन सहयोगियों की संचालन समिति या समन्वय समिति 'सुपर कैबिनेट' के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार यह सरकारी मशीनरी के कामकाज में कैबिनेट की भूमिका और स्थिति को कमजोर करती है।
3. क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय निर्णय लेने में क्षेत्रीय तथ्यों को सामने लाते हैं। वे केन्द्रीय कार्यकारिणी पर अपने हिसाब से काम करने का दबाव बनाते हैं, अन्यथा वे गठबंधन से हटने की धमकी देते हैं।
4. गठबंधन सरकारों के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं और चूकों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे दोषारोपण का खेल खेलते हैं ताकि सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से बच सकें।
5. नौकरशाही की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि होती है।
6. संसदीय शासन का मूलभूत लक्षण मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का गठबंधन सरकारों में ह्रास हुआ है। गठबंधन सरकार के घटकों में कार्यरत समरसता के अभाव ने इस प्रक्रिया को बाधा पहुंचायी है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

मिली–जुली सरकारों के लक्षण[6]–

मिली–जुली सरकारों के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं –

1. मिली–जुली सरकार में कम–से–कम दो भागीदार होते हैं। भागीदार दलों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।
2. भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं।
3. गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है।
4. मिली–जुली सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है, इसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता।
5. मिली–जुली सरकार की संकल्पना और प्रबंध में एक मूलभूत विकासशीलता होती है।

भारत में गठबंधन सरकारों की स्थिति (1977–वर्तमान)[7] –

अवधि	गठबंधन	प्रधानमंत्री (पार्टी)
1977–1979	जनता पार्टी	मोरारजी देसाई (कांग्रेस –(ओ)
1979–1980	जनता पार्टी (सेक्यूलर)	चरण सिंह (जनता (एस))
1989–1990	राष्ट्रीय मोर्चा	वी.पी. सिंह (जनता दल)
1990–1991	जनता दल सोशलिस्ट/समाजवादी जनता पार्टी	चन्द्रशेखर (जनता दल (एस)) या समाजवादी पार्टी
1996–1997	संयुक्त मोर्चा	एच.डी. देवगौड़ा
1997–1998	संयुक्त मोर्चा	आई.के. गुजराज (जनता दल)
1998–1999	भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन	ए.बी. वाजपेयी (भाजपा)
1999–2004	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)	ए.बी. वाजपेयी (भाजपा)
2004–2009	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)	मनमोहन सिंह (कांग्रेस)
2009–2014	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)	मनमोहन सिंह (कांग्रेस)
2014–2019	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)	नरेन्द्र मोदी (भाजपा)
2019–2024	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)	नरेन्द्र मोदी (भाजपा)
2024–वर्तमान	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)	नरेन्द्र मोदी (भाजपा)

प्रमुख समस्याएँ[8] –

गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में प्रशासनिक तंत्र के समक्ष उठने वाली मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं –

1. ऐसी सरकारों में विभिन्न दलों की मूलभूत वैचारिक भिन्नताओं के कारण लोकनीति की दृष्टि से ऐसी सरकारें निष्फल मानी जाती हैं। इसी कारण प्रशासन के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2. गठबंधन सरकारें न्यूनतम साझा समझौते पर कार्य करती हैं। इसके लिये संबंधित दलों को विशेष रूप से प्रमुख दल को चुनाव घोषणा–पत्र तक को तिलांजलि देनी पड़ती है। इस प्रकार प्रशासनिक पक्ष की उपेक्षा करते हुए न्यूनतम कार्यक्रम एक राजनीतिक दस्तावेज बन जाता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

3. साझा सरकारों में दूरगामी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से साझा सरकारें तात्कालिक आवश्यकताओं तथा समझौते के अनुरूप संचालित होती है।
4. साझा सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाता है। मनोवांछित अधिकारियों की नियुक्ति तथा अधिक मात्रा में स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के द्वार खोलते हैं।
5. गठबंधन सरकारों में सुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी सरकारों में दागदार सांसद, मंत्री, विधायक जब सत्तारूढ़ होते हैं तो प्रशासन की छवि अच्छी नहीं हो सकती और सुशासन की व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है।
6. सामान्यतः साझा सरकारें अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं। साथ में नौकरशाही अधिक प्रभावी हो जाती हैं। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी पर गठित तथा अस्थिर सरकारें कुशल, ईमानदार प्रशासन नहीं दे सकती हैं।
7. साझा सरकारों में प्रशासनिक सुधारों की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें प्रशासनिक सुधार शासन की प्राथमिकता सूची में स्थान नहीं बना पाते हैं।

सरकार[9] द्वारा लिए गए निर्णय उसके विभिन्न घटक दलों के निर्णय माने जाते हैं। मिली जुली सरकारों का अनुभव भी मिला जुला है। गठबंधन सरकार सहयोगी दलों से बहुत अधिक मात्रा में सहनशीलता और कर्तव्य परायणता की मांग करती हैं।

शोध के उद्देश्य –

1. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मिली जुली सरकारों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. संसदीय प्रजातंत्र के निष्पादन एवं राष्ट्रीय राजनीति पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना।
3. सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन कर मिली जुली सरकार के संचालन में आने वाली चुनौतियों के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की प्रविधि –

प्रस्तावित शोध कार्य में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, लेख पूर्व में हुए शोध अध्ययन आदि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में मिली–जुली सरकारों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के प्रभावों, चुनौतियों एवं उन चुनौतियों के लिए समाधानों तटस्थ विवेचना प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत शोध कार्य में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा तथ्यों की निष्पक्ष व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। शोध कार्य में पूर्ण निष्पक्षता, तटस्थ एवं तथ्यपरक विवेचना प्रस्तुत की गयी है।

निष्कर्ष –

भारत में गठबंधन सरकार के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह देश के लोकतांत्रिक ताने–बाने की एक अनूठी विशेषता है, जो अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रदान करती हैं।[10] भारत में गठबंधन सरकार के जितने सकारात्मक पक्ष हैं, उतने नकारात्मक पक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी सफलता पर संदेह बना रहता है। राजनीतिक दलों को विवेकशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, परिपक्वता, नैतिकता एवं ईमानदारी के गुणों के संग राजनीतिक सुचिता, पारदर्शिता एवं नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करनी होगी। राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत हित को त्यागकर राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देकर भारतीय लोकतांत्रिक

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

राजनीति में अस्थाई एवं अमजबूत सरकार के स्थान पर स्थाई और मजबूत सरकार के निर्माण हेतु प्रयत्न करना होगा जिससे भविष्य में सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके।

सुझाव–

मिली–जुली सरकार[11] को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सुझाव भिन्न प्रकार है –

1. गठबंधन के भीतर, सभी दलों को एक–दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और समन्वय बनाए रखना चाहिए।
2. गठबंधन बनाने से पहले, सभी भागीदार दलों को एक स्पष्ट और व्यापक गठबंधन समझौते पर सहमत होना चाहिए। इस समझौते में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
3. सभी दलों को अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं पर समझौता करने के लिए तैयार होना चाहिए।
4. मिली–जुली सरकार की स्थिरता बनाये रखने के लिए सभी दलों को सरकार के कार्यकाल के दौरान एकजुट रहने का प्रयास करना चाहिए।
5. मिली–जुली सरकार को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए।
6. गठबंधन के भीतर और जनता के साथ प्रभावी संचार बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
7. गठबंधन के भीतर विश्वास का माहौल बनाना आवश्यक है। सभी दलों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और सरकार के फैसलों में एक–दूसरे का समर्थन करना चाहिए।

संदर्भ स्रोतः–

1. डॉ0 मंडल, सत्य नारायण. (2020), भारत में गठबंधन सरकार :– एक विश्लेषण वाल्यूम नं0 07, पृ0 1247
2. डॉ0 सिरवी, सरोज. (2024), गठबंधन सरकार का महत्व और चुनौतियाँ, वाल्यूम नं0 06, पृ0 293
3. एम. लक्ष्मीकांत. (2019), भारतीय राज्यव्यवस्था, बाम्बे स्टडी आई.क्यू. एजुकेशन पब्लिकेशन, बॉम्बे, पृ0 745
4. पाठक, सतीश कुमार. (2024), ''गठबंधन सरकार : भारत में संघ एवं राजयों के संदर्भ में तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन'', वाल्यूम– 10, पृ0 11
5. डॉ0 फड़िया, बी.एल एवं डॉ0 फड़िया, कुलदीप. (2010), तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ0 334.
6. डॉ0 सिरवी, सरोज. (2024), गठबंधन सरकार का महत्व और चुनौतियाँ, वाल्यूम नं0 06, पृ0 296
7. अवस्थी एवं अवस्थी. (2016), भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा पृ0 520–521.
8. डॉ0 चौधरी, लाखा राम. (2017), भारत में गठबंधन की राजनीति, पंजाब केसरी।
9. डॉ. प्रभा, कंचन. (2023), ''संघीय सरकार के गठबंधन का महत्व'', वाल्यूम नं. 05, पृ. 856
10. सुषमा कुमारी. (2023), ''वर्तमान संदर्भ में गठबंधन की राजनीति एक अवलोकन'', वाल्यूम नं. 09, पृ. 76
11. पोखरिया, एस.पी., (2024), ''भारत में गठबंधन सरकार की सार्थकता''।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

वेबसाइट –

(1) en.wikipedia.org

(2) www.doubtnut.com

(3) www.sanskritias.com

(4) www.cambridge.org

(5) www.drishtiias.com